भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 396
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

396. श्री खगेन मुर्मु:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन स्कीमें बनाई गईं हैं-

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया)**: सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कुल ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता से फ़ेम इंडिया स्कीम, चरण-II अधिसूचित किया। इस स्कीम को 2 और वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

ii. **मोटर वाहन क्षेत्र के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने ₹25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय वाली ऑटोमोबिल क्षेत्र संबंधी पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को मंज़ूरी दी।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए ₹18,100 करोड़ के परिव्यय वाली पीएलआई स्कीम को 12 मई, 2021 को मंज़ूरी दी। इस स्कीम में देश में 50 गीगावॉट घंटे की एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम में 5 गीगावॉट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नांकित प्रमुख कदम उठाए गए हैं:-

i. फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए ₹1,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

ii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आदर्श भवन उप-नियमों तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में संशोधन जारी किये हैं।

iii. विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं।

*****